

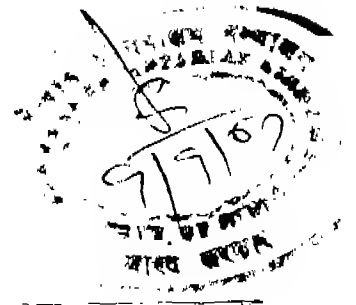


भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 325]
No. 325]

नई दिल्ली, सोमवार, जून 29, 1987/अषाढ़ 8, 1909
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 29, 1987/ASADHA 8, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 जून, 1987

आदेश

कां. प्रां. 649 (अ)/18चक/18कक/प्राई.डी.प्रार.ए./87:—
केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय औद्योगिक विकास
विभाग के आदेश सं.कां.प्रां. 613(अ)/18चक/18कक/प्राई.डी.प्रार.ए./76,
दिनांक 15 सितम्बर 1976 द्वारा इंडस्ट्रियल रिकन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन
आफ इण्डिया लिमिटेड कलकत्ता जिसे अब भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण
बैंक कहा जाता है को (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया
है) मैसर्स बंगाल पाटरीज लिमिटेड कलकत्ता के स्वामित्व वाले 45-हंगरा
रोड कलकत्ता और 3 पगलाबांगा रोड कलकत्ता स्थित औद्योगिक उप-
क्रमों के सम्पूर्ण प्रबन्धों को 15 सितम्बर 1976 से पांच वर्ष की अवधि
के लिये ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत किया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग)
के आदेशों द्वारा उक्त आदेश की अवधि समय-समय पर 30 जून 1987
तक जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी सम्मिलित है की अवधि अवधि के
लिए बढ़ा दी गई थी।

और केन्द्रीय सरकार की यह राय होने पर कि सर्वसाधारण के हित
में यह समीचीन था कि प्राधिकृत व्यक्ति उक्त औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध करना
जारी रखे उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 (1951
का 65) की धारा 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन एक
आवेदन कलकत्ता उच्च न्यायालय को दिया था जिसमें यह प्रार्थना की गई
कि ऐसा प्रबन्ध तारीख 30 सितम्बर 1987 तक जिसके अन्तर्गत
यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिये जारी रखा जाये।

और उक्त उच्च न्यायालय ने अपने तारीख 26 जून 1987 के
आदेशानुसार प्राधिकृत व्यक्ति को उक्त दोनों औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध
तारीख 30 सितम्बर 1987 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है
की और अवधि तक जारी रखने के लिये अनुज्ञात कर दिया था।

अतः केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 18कक के साथ
पठित 18चक की उपधारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए प्राधिकृत व्यक्ति को निर्देश देती है कि वह 30 सितम्बर
1987 तथा जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है की और अवधि के लिए
उक्त दोनों औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध करना जारी रखे।

[का स 2(19)/75-सी ए एम]

ए. वी. गोकक,
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 29th June, 1987

ORDER

S.O. 649(E)18FA/18AA/IDRA/87.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 613(E)/18FA/18AA/IDRA/76, dated the 15th September, 1976, the Central Government had authorised the Industrial Reconstruction Corporation of India Limited, Calcutta, now known as Industrial Reconstruction Bank of India (hereinafter referred to as the authorised person), to take over the management of the whole of the two Industrial Undertakings at 45, Tangra Road, Calcutta and at 3, Pagladanga Road, Calcutta, owned by Messrs Bengal Potteries Limited Calcutta, for a period of five years from the 15th September, 1976.

And, whereas, the duration of the said order was extended from time to time by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) for a further period upto and inclusive of the 30th June, 1987.

And, whereas the Central Government being of opinion that it was expedient in the interest of the general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertakings made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period upto and inclusive of 30th September, 1987.

And whereas the said High Court by its dated the 26th June, 1987 permitted the authorised person to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of 30th September, 1987.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of Section 18FA read with section 18AA of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised persons to continue to manage the said two industrial undertakings for a further period upto and inclusive of the 30th September, 1987.

[F. No. 2(19)/75-CUS]
A. V. GOKAK, Jt. Secy.